सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 209 राँची, गुरुवार, 16 चैत्र, 1938 (श०)
6 अप्रैल, 2017 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

23 मार्च, 2017

संख्या:-3/4/आई.डी/ईसीआई/पत्र/व्यवहारिक/विधिक/एस०डी०आर/खण्ड-2/2017-- यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों का उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, उक्त अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग हेतु नियमों के द्वारा उपबंधो को बनाया जा सकता है; तथा

2. यत:, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके । निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है; तथा

3. यत:, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49ज (3) तथा 49ट (2) (ख) में यह अनुबंधित है कि जहां किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिये जाते हैं, निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा तथा उनके द्वारा निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखाए जाने व असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इन्कार किया जा सकता है, तथा

4. यत:, उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपर्युक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने से ही होता है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर, मतदान के समय उनकी पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों को एक साथ प्रयोग करना होता है, तथा

5. यत:, निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध योजना के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी करने का निर्देश देते हुए दिनांक 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया है, तथा

6. यत:, असम, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल राज्यों के निर्वाचकों काफी हद तक उच्च प्रतिशत में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं, तथा

7. यत:, इसके अलावा, आयोग ने यह आदेश दिया है कि वर्तमान उप-निर्वाचनों की मतदान तिथि से पूर्व मतदाताओं को "**प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची**" बांटी जाएगी,

8. अत:, अब सभी संबद्ध घटकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, यह निदेश देता है कि 14 मार्च, 2017, 16 मार्च, 2017 एवं 17 मार्च, 2017 को अधिसूचित किए गए **जम्मू एवं कश्मीर में 02-श्रीनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं 03-अनन्तनाग निर्वाचन क्षेत्र, केरल में 06-मलप्पुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं असम में 113-धेमाजी (अ०ज०जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश में 36-भोरंज (अ०जा०) विधान सभा निर्वाचन**

क्षेत्र, मध्यप्रदेश में 09-अटेर एवं 89-बांधवगढ (अ०ज०जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में 216-कांथी दक्षिण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान में 79-धौलपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक में 214-ननजनगुड़ (अ०जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं 224-गुन्दलुपेट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडू में 11-डॉ. राधाकृष्णन नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखण्ड में 04-लिटिपाड़ा (अ०ज०जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, सिक्किम में 28-अपर बुरटुक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एवं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 27-राजौरी गार्डन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान उप-निर्वाचनों के लिए सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, मतदान स्थल पर मत डालने से पहले पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा:-

(i) पासपोर्ट

(ii) ड्राइविंग लाइसेन्स

(iii) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र

(iv) बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक

(v) पैन कार्ड

(vi) आधार कार्ड

(vii) आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड

(viii) मनरेगा जॉब कार्ड

(ix) श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड

(x) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज

(xi) निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची, एवं

(xii) सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सद्स्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र।

9. ईपीआईसी के संबंध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते मतदाता की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके । यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा जारी किया गया है, ऐसे ईपीआईसी भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए

जाएंगें बशर्ते निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान स्थल से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए । यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब मतदाता को उपर्युक्त पैरा 8 में वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तोवज को प्रस्तुत करना होगा ।

10. उक्त पैरा 8 में किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचन नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके **केवल** मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा ।

आदेश से,

के.एफ.विल्फ्रेड,
प्रधान सचिव ।

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एल० खियांग्ते,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रधान सचिव ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

23rd March, 2017

No. 3/4/ID/ECI/LET/FUNC/JUD/SDR/VOL.II/2017-- Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electors Photo Identity Card for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and

2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of Electors Photo Identity Card to electors bearing their photographs at State cost; and

3. Whereas, Rules 49H (3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electors Photo Identity Card under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Electors Photo Identity Card at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electors Photo Identity Card may result in the denial of permission to vote; and

4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Electors Photo Identity Card, where provided by the Election Commission at State cost, as the means of establishing their identity at the time of polling and that both are to be used together; and

5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993, directing the issue of Electors Photo Identity Card (EPIC) to all electors, according to a time bound programme; and

6. Whereas, Electors Photo Identity Card have been issued to a substantially large number of electors in the State of **Assam, Himachal Pradesh, Jharkhand, Jammu & Kashmir, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, NCT of Delhi, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, West Bengal**; and

7. Whereas, in addition the Commission has directed that '**Authenticated Photo Voters Slip**' shall be distributed to the electors before the date of poll for the current bye Elections;

8. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that for the current bye elections from **02-Srinagar Parliament Constituency & 03-Anantnag Parliament Constituency in Jammu & Kashmir, 06-Malappuram Parliament Constituency in Kerala, 113-Dhemaji (ST) Assembly Constituency in Assam, 36-Bhoraj (SC) Assembly Constituency in Himachal Pradesh, 09-Ater Assembly Constituency & 89-Bandhavgarh (ST) Assembly Constituency in Madhya Pradesh, 216-Kanthi Dakshin Assembly Constituency in West Bengal, 79-Dholpur Assembly Constituency in Rajasthan, 214-Nanjangud (SC) Assembly Constituency & 224-Gundlupet Assembly Constituency in Karnataka, 11-Dr. Radhakrishnan Nagar Assembly Constituency in Tamil Nadu, 04-Litipara (ST) Assembly Constituency in Jharkhand, 28-Upper Burtuk Assembly Constituency in Sikkim, 27-Rajouri Garden Assembly Constituency in NCT of Delhi,** which have been notified on **14 March, 2017, 16 March, 2017 and 17 March, 2017** all electors who have been issued EPIC shall produce the EPIC for their identification at the polling station before casting their votes. Those electors who are not able to produce the EPIC shall produce one of the following alternative photo identity documents for establishing their identity:-

(i) Passport;

(ii) Driving License;

(iii) Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Govt. PSUs/Public Limited Companies;

(iv) Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office;

(v) PAN Card;

(vi) Smart Card issued by RGI under NPR;

(vii) MNREGA Job Card;

(viii) Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour;

(ix) Pension document with photograph;

(x) Authenticated Photo Voter Slip issued by the election machinery; and

(xi) Official identity cards issued to MPs/MLAs/MLCs.

(xii) Aadhaar Card.

9. In the case of EPIC, clerical errors, spelling mistakes, etc. should be ignored provided the identity of the elector can be established by the EPIC. If an elector produces an Electors Photo Identity Card, which has been issued by the Electoral Registration Officer of another Assembly Constituency, such EPICs shall also be accepted for identification provided the name of that elector finds place in the electoral roll pertaining to the polling station where the elector has turned up for voting. If it is not possible to establish the identity of the elector on account of mismatch of photograph, etc. the elector shall have to produce one of the alternative photo documents mentioned in para 8 above.

10. Notwithstanding anything in Para 8 above, overseas electors who are registered in the electoral rolls under Section 20A of the Representation of the People Act, 1950, based on the particulars in their Passport, shall be identified on the basis of their original passport **only** (and no other identity document) in the polling station.

By order,

K F WILFRED,

PRINCIPAL SECRETARY

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 209--50